भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2536
जिसका उत्तर मंगलवार 01 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

विद्युत वाहनों का उत्पादन

2536. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में शीघ्र ही विद्युत वाहनों की संख्या बढ़ाकर कम से कम छः मिलियन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(ग) क्या विद्युत वाहनों की वर्तमान उत्पादन क्षमता उक्त आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगी?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): जी, हां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन वर्ष 2011 में और तत्पश्चात् राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 का अनावरण वर्ष 2013 में किया था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 के अंतर्गत 2020 तक 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करने का भारत सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

मिशन के एक भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] नामक स्कीम तैयार की है। यह समग्र स्कीम 2020 तक 6 वर्ष की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंत तक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और इसके विनिर्माणकारी पारिस्थितिकी-तंत्र को सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, स्कीम का चरण-I कार्यान्वित किया जा रहा है, जो मूलतः 01 अप्रैल, 2015 से आरम्भ होकर 31 मार्च, 2017 तक 02 वर्ष की अवधि के लिए था तथा अब इसकी अवधि का विस्तार 30 सितम्बर, 2017 तक आगे और 6 माह की अवधि के लिए कर दिया गया है।

चूंकि, फिलहाल फेम-इंडिया स्कीम पूरी तरह से संपूर्ण भारत में लागू नहीं है। इसलिए, यह विभाग उन वाहनों के आंकड़े रखता है जिनकी बिक्री स्कीम के फोकस क्षेत्र में मांग-सृजन के अंतर्गत की जाती है। फोकस के लिए शामिल किए गए इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की बिक्री के लिए मांग-प्रोत्साहन दिया जाता है। स्कीम के अंतर्गत, 26 जुलाई, 2017 की स्थिति तक कुल 1,50,550 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को यह प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है।

****